बिहार विधान परिषद्

191 वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

25 माघ, 1940 (श.)

वृहस्पतिवार तिथि ----------

14 फरवरी, 2019 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 10

1.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग	---	---	02
2.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	---	---	01
3.	गृह (आरक्षी) विभाग	---	---	01
4.	जल संसाधन विभाग	---	---	01
5.	लघु जल संसाधन विभाग	---	---	01
6.	परिवहन विभाग	---	---	01
7.	वित्त विभाग	---	---	02
8.	समाज कल्याण विभाग	---	---	01

कुल योग - 10

जिम्मेवार कौन

26. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि विभागीय लापरवाही से पटना स्थित वीरचंद पटेल जैसी वी.आई.पी. सड़क पर हरियाली बढ़ाने के लिये लगाये गये सैकड़ों पौधों की देख-रेख नहीं हो रही है, जिससे लगाये गये तमाम पौधे सूख गए हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि इस विशेष क्षेत्र में सूखे पौधों पर किसी की नजर नहीं जा रही है, जिससे पटना में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुँच गई है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बतलाएगी कि हरियाली को ध्वस्त करने के लिए कौन जिम्मेवार है और उन पर वह कौन-सी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

.....

शौचालय निर्माण में लापरवाही

27. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत एकमात्र अंबेडकर आवासीय विद्यालय सुगांव के तीन सौ छात्र अपनी प्रतिष्ठा को ताक पर रख कर नियमित खुले में शौच करने को मजबूर हैं;

(ख) क्या यह सही है कि छात्रावास के दो अलग-अलग दो मंजिला और तीन मंजिला भवन में रह रहे छात्रों के लिए 30 शौचालय का निर्माण कराया गया है, पर निर्णय में बरती गई अनियमितता के कारण पाईप, सीट तथा पानी टंकी फूट चुकी है तथा 300 छात्रों के बीच 2 चापाकल लगाया गया है जो कम गहरा होने के कारण प्रदूषित पानी देता है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकरात्मक हैं तो उक्त विद्यालय में अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं के अभाव में छात्रों को खेतों में शौच के चलते गांववालों के ताने सुनने पड़ते हैं, सरकार अरबों रुपये के खर्च के बावजूद निर्माण में बरती गई लापरवाही हेतु यदि कार्रवाई करना चाहती है तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

.....

मालखाने का स्थानांतरण

28. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर थाने के मालखाना का सारा सामान वहां पर अवस्थित मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च विद्यालय परिसर में वर्षों से पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या यह सही है कि इस संबंध में विद्यालय प्राचार्य एवं मेरे द्वारा संबंधित पदाधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी अभी तक वहां से मालखाने का सामान अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि विद्यालय परिसर में मालखाने का कबाड़ जमा रहने के कारण विद्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य बाधित है तथा परिसर के सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य भी बाधित है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस मालखाने को शीघ्रातिशीघ्र विद्यालय परिसर से स्थानांतरित करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

.....

अतिक्रमण मुक्त कबतक

29. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत थावे प्रखंड के पिठौरी मेन कैनाल से निकलकर नारायणपुर तक जाने वाली नहर चनावे जेल प्रशासन द्वारा अतिक्रमित कर दिया गया है, जिससे उक्त नहर में पानी का बहाव नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि जेल प्रशासन के अतिक्रमित कर देने के कारण उक्त नहर में पानी का बहाव नहीं होने से करीब दो पंचायत क्रमश: लक्षवार, फुल्गुनी के करीब सैकड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई नहीं हो पा रही है जिससे उक्त क्षेत्र के किसानों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कब उक्त नहर को चनावे जेल प्रशासन के अतिक्रमण से मुक्त कराकर किसानों के खेत तक नहर का पानी पहुंचाना चाहती है ? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

.....

प्रदूषण मुक्त

30. **श्री रामचन्द्र पूर्वे एवं श्री केदारनाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर में करीब 70% डीजल एवं 24 % पेट्रोल की गाड़ी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना आवागमन में हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वाहनों के कारण पटना देश का 10 वां प्रदूषित शहर बन गया है, जिसके कारण यहां के निवासियों को घुटन महसूस होने लगी है ;

(ग) क्या यह सही है कि 15 वर्षों की पुरानी डीजल एवं पेट्रोल गाड़ी के चलने से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार पटना शहर को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कौन-सा उपाय करना चाहती है ?

.....

नलकूप चालू कबतक

31. श्री रामचन्द्र पूर्वे : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परिहार प्रखण्ड के बराही, सरदलपटी, झपहा, मनपौर, बबुरवन,परबाहा, महादेवपट्टी, बहुअरवा गांव के राजकीय नलकूप वर्षों से यांत्रिक एवं विद्युत दोष के साथ नाला के ध्वस्त होने के कारण बंद हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नलकूपों के बंद होने से किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उक्त राजकीय नलकूपों को चालू कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

.....

योजना का लाभ

32. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि ग्राम परिवहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 42,315 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है ;

(ख) क्या यह सही है कि ग्रामीण इलाकों में यातायात के साधन उपलब्ध कराने के साथ बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार हेतु प्रत्येक पंचायत से पांच लोगों को देना है ;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग के लोगों को लाभ नहीं देना है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार सभी वर्ग के बेरोजगार युवक और युवती को ग्राम परिवहन योजना का लाभ दिलाना चाहती है यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

.....

कार्यवाही का अनुमोदन

33. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-1645 दिनांक-20.11.2018 द्वारा दिनांक- 10.10.2018 को आयोजित शासी परिषद् की 21 वीं बैठक की कार्यवाही प्रेषित की गई है ;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित कार्यवाही वित्त विभाग की सहमति के उपरांत ही बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा संबंधित कंडिकाओं में लिये गये निर्णय का पत्र निर्गत किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सही है कि दो माह से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी अभी तक वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण कार्य बाधित हैं ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित कार्यवाही का अनुमोदन कराते हुए लिये गये निर्णय का पत्र निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उतर –

(क) स्वीकारात्मक है।

(ख) स्वीकारात्मक है।

(ग) अस्वीकारात्मक है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद् के निर्णय से संबंधित संचिका दिनांक 26.11.18 को वित्त विभाग में प्राप्त हुई, जिसे कुछ पृच्छाओं के साथ दिनाक 16.1.19 को वापस किया गया। पुन: उक्त संचिका दिनांक 25.1.19 को वित्त विभाग में प्राप्त हुई। वित्त विभागीय मत अंकित कर संबंधित संचिका दिनांक 4.2.19 को लौटायी जा चुकी है ।

(घ) उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है ।

.....

राशि का भुगतान

34. **श्री सी०पी०सिन्हा** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अविवाहित इन्टर उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000/- रुपये देने का प्रावधान है ;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में प्रथम श्रेणी से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को 15,000/- रुपये देने का प्रावधान है ;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2016-18 में जे.डी.वीमेन्स कॉलेज,पटना से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अधिकांश छात्राओं को अबतक उनके बैंक खाता में राशि नहीं भेजी गयी है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि खण्ड 'क' एवं 'ख' में वर्णित राशि को खण्ड 'ग' में वर्णित छात्राओं के बैंक खाता में कबतक भेजी जाएगी ताकि वे आगे की पढ़ाई जारी रखें ?

.....

सूद का भुगतान

35. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार विश्व बैंक से ऋण लेती है और ये रकम,विभिन्न विभागों की योजनाओं में व्यय की जाती है ;

(ख) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी विश्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को ऋण के रूप में रकम दी गई है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि विश्व बैंक द्वारा दी गई राशि से कौन-कौन योजनाएं चलायी जा रही हैं और कितनी ऋण राशि के विरुद्ध अबतक विश्व बैंक को कितना सूद दिया गया है ?

उत्तर –

(क) स्वीकारात्मक।

सामान्यत: राज्य की वित्तीय आवश्यकता एवं परियोजनाओ की feasibility (संभाव्यता) को देखते हुए राज्य सरकार वाह्य वित्तीय संस्थाओं से भारत सरकार के माध्यम से ऋण प्राप्त करती है। विश्व बैक उन्हीं में से एक है। ऋण के रूप में प्राप्त राशि का व्यय एवं कार्यान्वयन विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है।

(ख) स्वीकारात्मक।

(ग) वर्ष 2018-19 में 07 (सात) परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से दिनांक31.01.2019 तक कुल 1180.14 करोड रूपये ऋण भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त किया गया एवं सूद के रूप में 56.01 करोड रूपये विश्व बैंक को दिया गया।योजनावार विवरणी अनुसूची 1 मे संलग्न है।

अनुसूची – 1

क. सं.	**परियोजना का नाम**	**वर्ष 2018-19 में प्राप्त ऋण राशि (दि. 31.01.2019 तक)**	**वर्ष 2018-19 में सूद के रूप में दी गई राशि (दि. 31.01.2019 तक)**
1.	बिहार कोशी बाढ़ सम्मुथान योजना (Bihar Koshi Flood Recovery Project) (Closed on 30.06.2018)	129.72 करोड़	2.69 करोड़
2.	बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना (Bihar Koshi Basin Development Project)	231.89 करोड़	8.45 करोड़
3.	अध्यापक शिक्षा परियोजना (Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar)	222.34 करोड़	16.81 करोड़
4.	बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण परियोजना (Bihar Integrated social Protection Strengthening Project)	82.16 करोड़	2.62 करोड़
5.	जीविका -2 (Bihar Transformative Development Project)	276.15 करोड़	15.65 करोड़

6.	बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना (Bihar Panchayat Strengthening Project)	34.18 करोड़	1.12 करोड़
7.	बिहार ग्रामीण पथ परियोजना (Bihar Rural Roads Project)	203.70 करोड़	8.67 करोड़
	कुल	**1180.14 करोड़**	**56.01 करोड़**

पटना

दिनांक 14 फरवरी, 2019

विनोद कुमार
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्